देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 03.06.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई, दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी सहित 12 लोग निलंबित।
- मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने पूरे राज्य में जबरखेत मॉडल को आधार बनाकर बड़े पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल विकसित करने के निर्देश दिए।
- चमोली जिले में थराली प्राणमती नदी पर जल्द बैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
- मौसम विभाग ने आज पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं–कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

कार्रवाई

हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले में दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इनमें हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को वर्तमान पद से हटाया गया है। इसके साथ ही नगर निगम की वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार और हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस मामले में अब तक कुल बारह लोगों को निलंबित किया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के आदेश दिये थे। रिपोर्ट मिलते ही भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में जिलाधिकारी की भूमिका संदेहास्पद पाई गई। पूर्व नगर आयुक्त ने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई। जबकि एसडीएम ने जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची। अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है। धामी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब उत्तराखंड में 'पद' नहीं, 'कर्तव्य' और 'जवाबदेही' महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा, तो कार्रवाई निश्चित है।

इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को यह संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की शून्य सहनशीलता की नीति का स्पष्ट प्रमाण है।

ईको टूरिज्म

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने पूरे राज्य में जबरखेत मॉडल को आधार बनाकर बड़े पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल विकसित करने के निर्देश दिये हैं। जबरख़ेत मॉडल पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी से ईको टूरिज्म को जोड़ने का एक बेहतरीन उदहारण है। मसूरी के पास स्थित जबरखेत नेचर रिज़र्व भारत का पहला निजी रूप से संचालित वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और ईको–पर्यटन को सफलतापूर्वक जोड़ता है। पूर्व में उजड़ चुके इस क्षेत्र को स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों की मदद से पुनर्जीवित किया गया, जहां अब सैकड़ों पक्षियों, तितलियों और जंगली जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

मुख्य सचिव ने इसी मॉडल को अपनाकर बड़े इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए करने पर जोर दिया है। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे स्थलों के चारों ओर छोटे–छोटे वन पर्यटन स्टेशन बनाए जाएं, जहां फॉरेस्ट ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, वाइल्डलाइफ सफारी, हेरिटेज ट्रेल, इको कैंपिंग और नेचर एडवेंचर जैसी गतिविधियां उपलब्ध हों।

मुख्य सचिव ने कहा कि इन डेस्टिनेशन को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाए और उनकी मार्केटिंग व संचालन की प्रभावी योजना तैयार की जा सके।

उन्होंने सुझाव दिया कि पहले चरण में 20 से 25 ऐसे स्थलों का चयन किया जाए जहां विकास की अच्छी संभावनाएं हों और जिनका विकास आसान हो। उन्होंने अस्सी के दशक से बंद नंदा देवी चोटी वाले क्षेत्र में इको टूरिज्म की संभावनाएं तलाशने के लिए भी अध्ययन करने को कहा।

बैली ब्रिज

चमोली जिले में थराली ब्लॉक के थराली–पैनगढ़–सूना मोटर मार्ग पर प्राणमती नदी पर जल्द बैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 में भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भारी बरसात के दौरान इस मोटर मार्ग में प्राणमती नदी पर बना मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। जिससे थराली गांव, सूना, देवल–ग्वाड़, पैनगढ़ और सुनाऊं गांव के दो हजार से अधिक ग्रामीणों की आवाजाही बाधित हो गई थी। निरीक्षण के बाद नया स्थान तय किया गया, लेकिन भूमि पर स्थानीय असहमति के कारण कार्य रुका रहा। ऐसे में ग्रामीणों की परेशानियों और आगामी मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान कर पुल निर्माण के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने लोक निर्माण विभाग को शीघ्र भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर पुल निर्माण करने के निर्देश दिए हैं।

दीक्षांत समारोह

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश में रोप वे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री, देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में तीन हजार से अधिक छात्र–छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को डॉक्टर ऑफ साईंस की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया।

मौसम

मौसम विभाग ने आज पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं–कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस अवधि में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं–कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र दौर के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से झोकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच, देहरादून में आज पूर्वाह्न तेज हवाओं के साथ रुक–रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है।

अनुबंध बढोतरी

प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेल विभाग में अनुबंध पर कार्यरत खेल प्रशिक्षकों के लिए राहत की खबर है। विभाग ने सभी जिला क्रीड़ा अधिकारियों को इन प्रशिक्षकों के कॉन्ट्रैक्ट को 2025–26 सत्र तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि इस आदेश से न केवल प्रशिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी, बल्कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग भी बिना बाधा जारी रह सकेगी।

वित्त सचिव

प्रदेश के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने राज्य कर विभाग के अंतर्गत विशेष अनुसंधान इकाईयों को कर–चोरी में संलिप्त फर्मों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कैटरिंग, ब्यूटीपार्लर, कारपोरेट इवेंट और बड़े होटलों एवं रिजार्ट से संबंधित सूचनाओं का संकलन कर कार्यवाही करने को भी कहा। राज्य कर विभाग के हल्द्वानी सम्भाग में कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में श्री जावलकर ने गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष संगत वर्ष में प्राप्त लक्ष्यों की समीक्षा के अलावा विभागीय विषयों पर चर्चा की। इस दौरान वित्त सचिव ने सचल दल इकाईयों को आवंटित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए भी विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

जल संरक्षण

जल संरक्षण अभियान–2025 के तहत स्प्रिंग एंड रिवर रीजुवनेशन अथॉरिटी–सारा के तत्वावधान में चम्पावत स्थित जिला सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, पुनर्भरण और पुनर्जीवन है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वर्षा जल संचयन के लिये आवश्यक प्रयास करें। उन्होंने बताया कि जिले में 98 जल स्रोतों की पहचान की गई है, जिनको जल्द ही पुनर्जीवित करने के प्रयास किये जाएंगे।